केस स्टडी

नंबर 5

केवल ऊँची शिक्षा नहीं आपको समय पर बोलना भी आना चाहिये

नामः सिल्बिया करकेट्टा

उम्रः 35 वर्ष

मुखियाः 2015 से

शिक्षाः 7वीं पास

अनुभवः 2004 से स्वयं सहायता समूह की सदस्य

ग्राम पंचायतः पश्चिमी तेनसार

पंचायत समितिः केरसाई

जिलाः सिमडेगा

राज्यः झारखण्ड

सिल्बिया करकेट्टा एक स्वतंत्र और निडर महिला हैं जो पश्चिमी तेनसार ग्राम पंचायत की मुखिया भी हैं। पश्चिमी तेनसार झारखण्ड के सिमडेगा जिले में आने वाले केरसाई प्रखण्ड की एक ग्राम पंचायत है। अपने जीवन के शुरूआती दौर के बारे में बताते हुये सिल्बिया करकेट्टा कहती हैं कि 2004 में उन्होंने ग्राम पंचायत में बनाये गये स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में पहली सार्वजनिक भूमिका निभायी थी। कुछ ही दिनों के बाद समूह की अन्य 14 सक्रिय महिला सदस्यों के साथ मिलकर उन्होंने राशन की एक दुकान शुरू की। उनके अनुसार वह समाज के लोगों के लिये बहुत काम करना चाहती थीं लेकिन दुकान पर इसके लिये अवसर कम था। 2010 में राज्य में पंचायतों के लिये आयोजित चुनाव के दौरान उन्हें एक अवसर दिखाई दिया। उन्हें अपने वार्ड में विकास के बहुत काम नहीं दिखायी दे रहे थे तो उन्होंने वार्ड मेंबर के पद के लिये चुनाव लडने का फैसला किया। हालांकि उस चुनाव में सिल्बिया करकेट्टा हार गयीं किन्तु इससे उनकी कहानी खत्म नहीं हुई।

2015 में हुये ग्राम पंचायत के चुनाव में उन्होंने मुखिया के पद के लिये चुनाव लड़ने की ठानी। इस बार मुखिया के पद के लिये 8 महिलाओं ने पर्चा दाखिल किया था और उनमें से अधिकांश सिल्बिया करकेट्टा से अधिक पढ़ी–लिखी थीं। कुछ ने तो 12वीं या स्नातक तक की पढ़ाई भी की थी। शुरू में तो सिबिया को डर भी लग रहा था कि पता नहीं चुनाव जीत पायेंगी कि नहीं। लेकिन क्योंकि उनके पास मुखिया के रूप में गाँव के विकास का एक लक्ष्य था तो लोगों ने उनको वोट दिया और उन्होंने चुनाव जीत लिया।

चुनाव जीतने के साथ ही सिल्बिया करकेट्टा के सामने नयी चुनौतियाँ आने लगीं। सिल्बिया बताती हैं कि चुनाव जीतने के कुछ ही दिन बाद एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ता उनके पास आये और बोले कि आप राशन की दुकान चलाती हैं और चुनाव जीत गयीं हैं इसलिये 5 लाख रूपये दो। उनके आस–पास के लोगों ने भी उन्हें डर से यही सलाह दी कि पार्टी के कार्यकर्ता नुकसान पहुँचा सकते हैं इसलिये उन्हें पैसा दे दो। लेकिन सिल्बिया ने ऐसा नहीं किया बल्कि उन्होंने सिमडेगा जाकर जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में जाकर प्राथमिकी दर्ज कराई। उनकी शिकायत के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हुई और उन्हें न्याय मिला। सिल्बिया हँसते हुये बताती है कि उन्हें सारी ताकत और विश्वास मुखिया के पद पर चुने जाने के कारण मिला।

ग्राम पंचायत में अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हुये सिल्बिया बताती हैं कि उनके ग्राम पंचायत में 574 शौचालय बनने हैं जिनमें से लगभग 100 शौचालय महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मन. रेगा) के सहयोग से बनाये गये हैं। उनके अनुसार शेष शौचालयों का निर्माण जल सहिया कोष से होगा (शायद उन्हें स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पूरी जानकारी नहीं है)। उनके अनुसार ग्राम पंचायत में तालाब गहरीकरण, डोभा निर्माण, खेतों में सुधार का काम, मेड़ बंधान जैसे काम मनरेगा में किये गये हैं। सिल्बिया करकेट्टा के अनुसार ग्राम पंचायत में चल रही सभी योजनाओं में उनकी मुख्य भूमिका कामों की निगरानी करना और मजदूरी का सही समय पर भुगतान करवाना है। ग्राम पंचायत में आने वाली राशि के उपयोग का फैसला भी उनके द्वारा किया जाता है। सिल्बिया बताती हैं कि उनके पास एक स्कूटी है और उसी पर घूमते हुये उनके द्वारा सारे कामों की निगरानी की जाती है। जरूरत पड़ने पर रोजगार सेवक को भी सिल्बिया अपने साथ ले जाती हैं।

मनरेगा में हुआ तालाब निर्माण

सिल्बिया करकेट्टा को राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, रांची से दो बार प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्हें विकास केन्द्र सिमडेगा से भी शौचालय निर्माण पर प्रशिक्षण दिया गया है। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान से उन्हें मुखिया के रूप में काम करने और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है। सिल्बिया के अनुसार प्रशिक्षण पाने के बाद उन्होंने शौचालय निर्माण की सामग्री को मंगाया और सभी वार्ड मेंबरों के बीच में बाँटा लेकिल वार्ड मेंबरों के द्वारा ठीक से काम नहीं किये जाने के कारण उन्होंने उनसे सारा काम वापस ले लिया। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में विकास का काम रूक गया। उनके अनुसार जब दूसरी बार पैसा आया तो उन्होंने किसी को कोई काम नहीं दिया और सारा काम खुद से करवाया। इससे वार्ड मेंबर नाराज भी हो गये। ग्राम पंचायत की मीटिंग में वार्ड मेंबर कहते हैं कि 'जब मुखिया सब कुछ कर रही है तो हम लोग क्या करेंगे?' सिल्बिया करकेट्टा कहती हैं कि वह तो काम करना चाहती हैं लेकिन लोगों का सहयोग उन्हें नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत के सदस्य कहते हैं कि पहले हम लोग दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे उसके बाद मुखिया का हस्ताक्षर होगा'।

14वें वित्त आयोग की राशि से नाली निर्माण

ग्राम पंचायत के कामों के बारे में और बताते हुये सिल्बिया करकेट्टा कहती हैं कि ग्राम पंचायत की सभी जरूरतों के आधार पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को जानकारी दी जाती है। उनके ग्राम पंचायत में 150 परिवारों को पेंशन का लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि उनके गाँव में पानी की कमी को देखते हुये 10 हैण्ड पम्प को लगाने की जानकारी प्रखण्ड के स्तर पर दी जा चुकी है। उनके अनुसार 14वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि से गाँव में दो जगह नाली निर्माण और पंचायत भवन के चारो ओर दीवार निर्माण का काम किया जा चुका है। ग्राम पंचायत में इस संबंध में सभी दस्तावेज उपलब्ध हैं। उनके अनुसार योजना बनाओ अभियान (ग्राम पंचायत डेवलपमेन्ट प्लान) के अन्तर्गत योजनाओं को बनाया गया है और प्राथमिकतायें भी तय की गयीं हैं। इससे संबंधित दस्तावेजों को भी विकास खण्ड कार्यालय और जिला स्तर पर भेजा गया है।

अपने ग्राम पंचायत में स्कूल और आंगनबाड़ी के बारे में बताते हुये सिल्बिया कहती हैं कि उनके द्वारा प्रायः यह देख जाता है कि खाना ठीक से बन कर सभी बच्चों को दिया गया कि नहीं। स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति पर भी उनके द्वारा ध्यान दिया जाता है और उनकी अनुपस्थिति होने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाती है। सिल्बिया बताती है कि उनके ग्राम पंचायत में बच्चों के लिये टीकाकरण का कार्यक्रम भी चलाया गया था।

सिल्बिया करकेट्टा के अनुसार यदि उन्हें मनरेगा और 14वें वित्त आयोग के बारे में और जानकारी दी जाय तो उनके ग्राम पंचायत में और बेहतर काम किया जा सकता है।

गाँव की बालिकायें विद्यालय जाते हुये